ISSN: 2349-7637 (Online)
Volume-1, Issue-4, November 2014
RESEARCH HUB – International Multidisciplinary Research Journal
Research Paper
Available online at: www.rhimrj.com

नक्सलवाद का बदलता स्वरूप और भारत के लिए उभरती चुनौतीयॉ

विरेन्द्र सिंह[1st]
शोध छात्र (राजनीति विज्ञान विभाग)
वर्धमान महावीर खुला विश्व विद्यालय
कोटा, राजस्थान, भारत

प्रो. करन सिंह[2nd]
राजनीति विज्ञान विभाग
वर्धमान महावीर खुला विश्व विद्यालय
कोटा, राजस्थान, भारत

शोध सारांश: *भारत में आतंकवाद बहुत पुराना है किन्तु इस वैश्वीकरण के युग में इसने एक नया और भयावह रूप में राज्यो के समक्ष सुरक्षा के संकट खड़े किये है, क्या एक राष्ट्र इसका सामना कर सकता है अथवा नही इस प्रकार की नई समस्या नक्सलवाद है। जो कि वर्तमान समय में भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।*

नक्सलवाद कोई आतंकवाद का प्रकार नही था यह तो पहले पं. बंगाल सिलीगुड़ी संभाग के एक छोटे से गांव नक्सलवादी के नाम से जुड़ा हुआ है, जहॉ 1966–67 में आदिवासियो ने भू स्वामीयो के खिलाफ हथियार उठा लिए थे, इसके बाद यह आन्दोलन धीरे धीरे देश के अन्य क्षैत्रो में फैल गया और इस नक्सलवादी आन्दोलन के संस्थपक चारू मजुदार ने यह भी नही सोचा होगा कि सामाजिक बदलाव का यह संघर्ष एक दिन इस प्रकार का आतंकी रूप में पहुॅच जायेगा कि उनके लोग क्रान्तिकारी की बजाय आतंकवादी कहलायेगा।

आज वर्तमान समय नक्सलवाद पिछले लगभग 50 वर्ष में पं. बंगाल से शुरू होकर इतना विकृत रूप धारण कर चुका है जिसकी गति इस प्रकार बढ रही है कि आगे के 10 वर्षो में पूरे भारत में फैल जायेगा। यह नक्सलवाद पं. बंगाल, छत्तीसगढ, उड़ीसा, आन्ध्रप्रदेश, झारखण्ड, बिहार, के क्षेत्रो में नक्सलियो का समान्तर राज्य कायम है यह आतंक की समस्या भारत की आन्तरिक सुरक्षा के खिलाफ सबसे बड़ी समस्या व खतरा है क्योंकि साम्यवाद की यह धारा जिसे लेनिन ने एक बार शिशु विकृति कहा था, यह दुश्मनो के कत्ले आम में विश्वास करती है।

नक्सलवाद से प्रभावित देश के लगभग 170 जिलो में कुछ हिस्से मुक्त क्षेत्र सरीखे बन चुके है, नक्सलवादी आग की चिंगारीया भारत के 40 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में फैल चुकी है– नक्सली आन्दोलन विशेषज्ञो तथा विचारको की दृष्टि से कश्मीर में आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक है नक्सलवादी आतंक।

प्रस्तावना

नक्सलवाद मुख्य रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व प्रशासनिक भ्रष्टाचार के शीर्षक से जुड़ा है। नक्सलवादी आन्दोलन का नाम नक्सलवादी होना मुख्य कारण स्थान से जुड़े होना है। नक्सलवाद नक्सलवादी से बना है यह पं. बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित नक्सलवादी गांव से जुडा है, यह क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है यहॉ 1966–67 में वहॉ के आदिवासियो ने साम्यवाद को समाप्त करने हेतु से प्रेरित होकर संघर्ष शुरू किया, इस आन्दोलन के प्रमुख उग्र नेता चारू मजुमदार कानू सान्थाल, जगल सन्थाल, कदम मलिक, मुजी बुर्रहमान थे, इन्होने 1967 में आदिवासियो के लिए भू स्वामियो के खिलाफ हथियार उठा लिये थे, इसके बाद यह आन्दोलन धीरे धीरे पूरे देश के अन्य क्षैत्रो में फेलने लगा, धीरे धीरे आगजनी, लूट मार तथा गोली मारने के घटनाओ के कारण इस क्षैत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल समाप्त हो गयी, पुलिस हस्तक्षेप बिल्कुल नही रहा और संघर्ष अत्यधिक उग्र हो गया ।

भागमभाग एवं सही नेतृत्व के अभाव में तथा राज्य सरकार के प्रभावी दबाव के कारण अपने मूल स्थान पश्चिम बंगाल में यह आन्दोलन पनप नही सका, लेकिन यह आन्दोलन एक जैसी जगह की तलाश में जुड़ गया जहॉ नक्सलियो के छिपने एवं कुट योजना बनाने हेतु जंगल एवं घाटीयॉ विशेष रूप से उपलब्ध थी। वहॉ इसका विकास तीव्र गति से विस्तार हुआ यही कारण ह कि नक्सलवादी आन्दोलन आज देश के अनेक हिस्सो में फैल गया जैसे कि मध्य प्रदेश, बिहार, आन्ध्रप्रदेश, छत्तीसगढ, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडू, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रो में एक चुनौती बना हुआ है।

आज वर्तमान समय में नक्सलवादी एक ऐसी योजनाबद्व संगठन बन चुका हैं की उसके पास वर्तमान समय के कुशल सूचना तंत्र विशेष प्रशिक्षण एवं आधुनिक शास्त्र प्रणाली भी है।

आज वर्तमान समय में नक्सलवाद का स्वरूप इतना विकराल रूप धारण कर चुका है कि भारत के सभी राज्य इसकी चपेट में आते जा रहे है, आज भारत में करीब 20000 नक्सली उग्रवादी सक्रीय है नक्सलवाद का नाम सुनते ही इनकी हिंसक प्रवृति का विचार दिमाग में आता है, वर्तमान में लगभग भारत के 640 जिलो मे से 170 जिलो में नक्सलवादी समस्या से ग्रस्त है, यह भारत के 40 प्रतिशत भू भाग में फैल चुका है और अनेक प्रकार नक्सलवादी संगठनो का निर्माण हो चुका जो निम्न है। पीपुल्स वार ग्रुप (पी डबलू जी), पीपुल्स गुरिल्ला आर्मी (पी जी ए), माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (एम. सी. सी.) झारखण्ड लिबरशन फ्रट (जे एल एफ), मजदुर किसान संघर्ष समिति सी. पी. आई. (एम एल) आदि मुख्य रूप से सक्रिय संगठन है जो कि देश में आन्तरिक शांति व स्थिरता को बनाये रखने के लिए इस समस्या का निदान आवश्यक व महत्वपूर्ण है इस नक्सलवादी समस्या के बढने के मुख्य कारण निम्न है।

नक्सलवाद के कारण

- बढती बेरोजगारी के कारण युवा नक्सली आन्दोलन से जुड़ते जा रहे है ।
- भूमि संबंधी समस्या आदिवासियो को उनकी ही जमीन से बेहाल कर दिया जाना जिसके द्वारा उनका पालन पोषण होता था।
- अमीर व गरीबो के बीच बढती विभाजन रेखा, या भू स्वामियो तथा मजदुरो के बीच आर्थिक असन्तुलन का होना।
- मौलिक सुविधाओ सम्बन्धी समस्या नक्सल प्रभावित क्षैत्रो में मूलभूत सुविधाओ का अभाव जैसे सड़क परिवहन, रेल परिवहन, आवास संबंधी समस्या अस्पताल, बिजली आदि का अभाव है जिस कारण स्थानीय नागरिको में सरकार के प्रति असन्तोष उत्पन्न होता है।

2014, RHIMRJ, All Rights Reserved

- नक्सलवादीयो को बाहरी देशो से आर्थिक मदद प्राप्त होना।
- शिक्षा संबंधी समस्या नक्सलवाद प्रभावित राज्यो में शिक्षा का अत्यधिक होने के कारण वहॉ की जनता अशिक्षित होने से नक्सली बहला फुसलाकर अपने से मिला लेते है तथा एक ऐसी शिक्षा का अभाव जो लोगो में देश प्रेम की भावना जाग्रत करने के साथ साथ लोगो को स्वरोजगार के लिए भी तैयार करे।
- न्यायिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था सही समय पर न्याय न दे पाने में असफल होने के कारण भी नक्सली समस्या बढती जा रही है।
- **भ्रष्टाचार–** नौकरशाही के भ्रष्ट होने तथा असक्षम पुलिस बल के अत्याचारो से प्रभावित लोग इससे जुड़ते है तथा देश मे व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण से इन प्रभावित क्षेत्रो का विकास नही हो सका।
- **राजनैतिक कारण–** राजनेताओ द्वारा स्वार्थ परक राजनीति व नक्सलवादी संगठनो को आर्थिक मदद के कारण भी नक्सली समस्या बट रही हैं।
- **प्रशासनिक कारण–** पुलिस तथा विभिन्न गुप्तचर एजेन्सीयो में आपसी तालमेल की कमी के कारण भी नक्सलवाद बढ रहा है।
- शोषण के कारण भी जैसे राजस्व कमियो फारेस्ट व पुलिस कर्मियो द्वारा यहा की जनता का आर्थिक मानसिक शोषण करती है जिससे परेशान होकर आम आदमी नक्सली बनने के लिए मजबूर हो जाते है।
- नक्सलियो के अधिक स्त्रोत पर प्रतिबन्ध न लगाना।
- सामाजिक कल्याण की योजना सही समय पर शुरू नही होने के कारण भी नक्सली समस्या बढती जा रही है।
- विस्थापित लोगो को से सहायता उपलब्ध नही कराने के कारण भी।
- एक तरफ हमारे सुरक्षा बलो के पास आधुनिक अस्त्र शस्त्रो का अभाव है वही दुसरी तरफ उनकी कार्यवाहीयो मे बाधक बनने वाले राजनैताओ के आदेशो के कारण भी हमारे सुरक्षा बल नक्सली संगठनो को कुचलने के लिए प्रभावशाली कार्यवाही नही कर पाते।
- लोकतान्त्रिक खुलेपन के कारण धन व हथियारो को आसानी से विदेशे से प्रवेश।
- मानवाधिकारो व जनमत के प्रति संवेदनशीलता के कारण सशक्त कार्यवाही संभव न हो पाना।

नक्सलवाद से भारत में प्रभावित क्षेत्र

एक समय पं. बंगाल से शुरू अब भारत के कई राज्यो में फेल चुका है और फेलता जा रहा है।

प्रमुख रूप से प्रभावित क्षेत्र

अति संवेदनशील राज्य	**जिले**
1 छत्तीसगढ	बस्तर, जगदलपुर, कॉकेर, राजनन्दगॉव, सरगुजा, दतेवाड़ा, जसपुर, कवर्द्धा आदि
2 बिहार	औरंगाबाद, जहसाबाद, रोहताम, बक्सर, पटना, गया, सहरसा, खगड़िया बॉका जमुई जिले
3 झारखण्ड	पलामू, गढवा, लतेहर, गुमला, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा आदि
4 आन्ध्रप्रदेश	रायलसीमा, और दक्षिणी तटीय जिले
5 उड़ीसा	मलकनगिरि, कोरपुट, गजपति, रामगढ, नवरंगपुर, और, मयूरभंज जिले
6 महाराष्ट्र	गढजिरौली, भण्डरा, और चनद्रपुर जिला
7 तेलंगाना	उत्तरी और दक्षिणी तेलंगाना
मध्य रूप से प्रभावित क्षेत्र	
8 मध्य प्रदेश	बालाधार, डिडोली, और मण्डला जिले
9 पं. बंगाल	मिदनापुर, पुरूलिया, और बाकुडा जिले
10 उत्तर प्रदेश	चन्दोली, सोनभद्र, मिर्जापुर जिले
11 केरल	
12 कर्नाटक	
13 तमिलनाडू	
आंशिक रूप से प्रभावित क्षेत्र	
15 हरियाणा	
16 राजस्थान	
17 पंजाब	
18 उत्तराखण्ड	

भारत में व्याप्त नक्सलवादी आतंकवाद के विस्तार मे पड़ोसी देशो की भूमिका

चीन– चीन भारत की विकासशीलता से नाखुश रहा है क्योंकि चीन विश्व में तो नही परंतु एशिया मे तो न. एक बना रहना चाहता है, एशिया महाद्वीव में चीन की प्रतिस्पर्धा जापान, रूस, भारत से है, वह भारत को पिछाड़ने में विशेष रूचि रखता है इसलिए वह भारत को इतना अव्यवस्थित कर देना चाहता है कि भारत अपने देश की आन्तरिक चुनौतियो में उलझा रहे और वह अपनी अन्तराष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति दर्ज न करा सके।

एक तरफ तो भारत के साथ वार्तालाप का नाटक रचता है और दुसरी तरफ गुप चुप तरीके से बड़ी सुनियोजित राजनीति के साथ चीन यहॉ के नक्सलवाद को मजबूत करने मे लगा है वह पूर्वोतर सहित सभी नक्सली गढो में चुप चाप मदद देता रहता है और नई नई समस्याओ का पैदा करता है तथा यहॉ के कम्यूनिस्टो को वैचारिक समर्थन देकर उनहे बदलाव के लिए उकसाता रहता है।

2014, RHIMRJ, All Rights Reserved
ISSN: 2349-7637 (Online)

नेपाल– नेपाल के माओवादीयो ने भारत में व्याप्त नक्सलियो को एक नई दिशा दी है। नेपाल के माओवाद ने वहॉ की राजव्यवस्थ को खत्म किया और वहॉ पर भी लोकतान्त्रिक सरकार संकट में आ गयी है यदि वह माओवादियो को सत्ता से दूर रखती है तो नेपाल फिर संकटो के दौर मे घिर जायेगा। और यदि उन्हे साथ लेकर चलती है तो माओवादी उसे निष्पक्ष व गणतांत्रिक तरीके से चलने नही देंगे।

कम्यूनिटी पार्टी ऑफ नेपाल और माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेपाल की बागडोर अपने हाथो में लेना चाहते है यदि ऐसा हुआ तो भारतीय माओवाद की नेपाली माओवादी हर संभंव मदद करने का प्रयास करेगा और अवैध रूप कारोबार करने का प्रयास करेगा न केवल रेड कोरी डोर इलाके मे बल्कि सम्पूर्ण भारत मे अवैध कारोबार को बढावा देगा। तब यहॉ की आर्थिक, राजनैतिक , व सामाजिक स्थिति अधिक भयानक हो जाएगी।

बांगलादेश – बांग्लादेश भारत मे सक्रिय रूप से कट्टरपंथ्थियो की मदद करता रहता है पूर्वोत्तर राज्यो सहित पं. बंगाल व अन्य पड़ोसी राज्य मे अवैध कारोबार करता रहता है इसलिए पाक. की खुफिया एजेन्सी (आई. एस. आई.) इनकी मदद करती रहती है और भारत में आतंकवादी गतिविधियां संचालित करने का प्रयास बांग्लादेश करता रहता है बांग्लादेशी लोग अपना नाम बदलकर कई आतंकवादी संगठन के लिए काम कर रहे है ये लोग बंग्लादेशी जेहादी संगइन हरकत उल जेहाद (हुजी) एवं जाग्रत मुस्लिम बांग्लादेश (जे एफ बी) से लिंग बनाकर उनकी मदद कर रहे है और यहॉ के नक्सलियो को उग्रवाद के लिए धन एवं हथियार दे रहे है।

श्रीलंका – भारत मे कई नक्सली विस्फोट गतिविधियो से उनके श्रीलंकाई उग्रवादी लिट्टे से सांठ गांठ का पता चला है जमीनो मे सुरंग और आधुनिक हथियारो का प्रशिक्षण व गुटो मे महिलाओ की भर्ती यह सब लिट्टे संगठन की तर्ज पर हो रहा है, यह श्रीलंकाई प्रयास से कम नही है वैसे भी देखा जाऐ तो लिट्टे उग्रवादीयो को चीन मदद करता रहता था चीन साम्यवादी देश है अतः भारत के माओवादी लिट्टें को अपना सहयोगी मानते है। और एक बात यह है कि लट्टे चाहता है कि तमिलनाडू से नेपाल और भूटान तक रेड कोरीडोर सुरक्षित बना रहे है ताकि वह जमीनी रास्ते का प्रयोग र नक्सलियो की मदद से वह चीन से सम्पर्क बनाये रख सके इसलिय वह नक्सलियो की भरपूर मदद करता है।

भारत सरकार के वर्तमान कानून व नीतियॉ और उनकी स्थिति तथा नियन्त्रण की कोशिशें

भारत सरकार तथा राज्य सरकार नक्सलवादी इलाको मे योजनाओ को बहुत अधिक बढावा दे रहे है सर्व शिक्षा अभियान योजना मे अन्तर्गत केन्द्र सरकार पिछडे व प्रभावित पूर्वोत्तर राज्यो को 90:10 (केन्द्र व राज्य) के मध्य शार्शि प्रदान कर रहा है तथा तकनीकी शिक्षा को बढावा देने के लिये भी विशेष रूप से तकनीक शिक्षा तथा रोजगाार देने का प्रयास भारत सरकार कर रही है।

मओवादीयो से मुकाबले के लिए हजारो की संख्या मे विशेष पुलिस अधिकारीयो को तैनात किया जा रहा है इसके साथ साथ केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल (स्पेशल नक्सली क्षेत्र हेतु) ट्रास्क फोस का गठन व विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है आदिवासी व उच्चवर्ग को सुरक्षा व सुविधाएं दी जा रही है। राज्य सरकारे भी अपनी सुरक्षा हेतु नक्सली प्रभावित क्षेत्रो के लिए स्पेशल सुरक्षा फोर्स का गठन कर रही है। सलवा जुडूम सशस्त्र प्रकोष्ठ जैसे संगठन खड़े होकर नक्सलियो को चुनौतियां देने की कोशिश कर रही है।

सभी प्रभावित जिलो मे सुरक्षातंत्र मजबूत करने और विशेष पुलिस बल गठित करने पर जोर दिया जा रहा है ग्रहमंत्रालय ने कई जगहो पर सी आर पी एफ (रिजर्व पुलिस बल) और बी एस एफ (सीमा सुरक्षा बल) तथा एस एस बी (सीमा सशस्त्र बल) की कई बटालिने तैनात की है फिर भी इस अनियंत्रित युद्व को जीतने मे सफल नही हो पाये है बेहतर सशस्त्रो से सुसज्जित पुलिस बल के गठन के साथ ही माओवादीयो द्वारा उठाये जा रहे सामाजिक मुद्दे का हल भी ढुंढना जरूरी है।

राज्य सरकारो के प्रयासो को अगर देखे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने नक्सली इलाको मे पुलिसकर्मियो की सुरक्षा के लिए बुलेटप्रुफ चेक पोस्ट बनाने और लेसर युक्त स्नाइपर राइफल देने की कोशिश तेज कर दी है इन बुलेट प्रुफ चेक पोस्टो को एके 47 की गोलियां भी नही भेद पायेगी साथ ही जासुसो और एस पी ओ की संख्या बढाने का प्रयास भी हो रहा है और दुसरी तरफ भारत सरकार विभिन्न सरकारी योजनाओ के पैकेट नक्सली प्रभवित राजयो को प्रदान करने का प्रयास कर रही है तथा केन्द्र सरकार नक्सली प्रभावित क्षेत्रो मे वहॉ की मूलभूत आवश्यकताओ की पूर्ति हेतू विशेष पैकेअ प्रदान कर रही है।

भारत सरकार हिंसा छोड़ने वाले नक्सलियो को ईनाम देने जा रही है केन्द्र ने नक्सलवाद प्रभावित प्रदेशो से ऐसी ही नीतियां बनाने को कहा है जैसी केन्द्र ने 2 वर्ष पहले घोषित की थी इस नीति के तहत ऐसे नक्सलियो को लगभग 2 लाख का पैकेज देने की घोषणा की गई थी। जो हथियार डालेंगे केन्द्र सरकार की नीति के तहत आत्मसर्मपण करने वाले हर नक्सली को तात्कालिक तौर पर 1.5 लाख रूपये का ईनाम लगभग 3 साल तक के लिये व्यवसायिक प्रशिक्षण के दौरान 3000 रूपये मासिक वेतन और हथियार सौपने पर ईनाम दिये जाने की बात की थी इस नीति के तहत जो नक्सली आत्म समर्पण करेंगे उनके नाम पर बैंक में 1.5 लाख रूपये जमा कराये जायेंगे, जिसे वे 3 साल बाद निकाल सकते है, यह उनमे व्यवहार के आधार पर ही हो सकेगा जिसका अधिकारी प्रमाण पत्र देगा।

नक्सलवाद के दुष्प्रभाव

- नक्सलवाद सम्पूर्ण मानवीय सभ्यता को व्यापक रूप मे प्रभावित कर रहा है वह मानवोचित गुणो जैसे दया, करूणा, सहानुभूति, सुख व शान्ति को धीरे धीरे नष्ट करता जा रहा है।
- कुछ नक्सवादी क्षेत्र पर्यटन का महत्वपूर्ण स्थान रखते है जैसा कि जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आदि तो वहॉ का पर्यटन उद्योग एकदम मे ही चौपट होता जा रहा है क्योंकी नक्सलियो के डर से पर्यटको का आना जाना बन्द होता जा रहा है।
- नक्सलवादियो की इस आग में कई निर्दोष लोगो की जाने भी चली जाती है जैसे मासूम बच्चो, बुढो, व महिलाओ के प्रति भी कोई दया भाव नही रखते और उन्हे बेरहमी से मारते है जिससे असहाय परिवार उजड़ जाते है और कितने ही सुहाग उजड़ जाते है।
- नक्सलवादियो द्वारा देश के सैनिक व पुलिसकर्मी भी मारे जाते है और आन्तरिक सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हो जाती है।
- नक्सलवाद सामान्य लोगो मे आतंक का भय पैदा करता है, जिससे लोगो के दिल मे डर और असुरक्षा की भावना भी हर समय विद्यमान रहती है। जिससे डर से वह स्वभाविक जीवन व्यतीत नही कर पाते है।

2014, RHIMRJ, All Rights Reserved
ISSN: 2349-7637 (Online)

- नक्सली समस्या से निपटने के लिये सरकार को सैनिक बल व पुलिस बल को बढाने के लिए काफी धन खर्च करना पड़ता है जिस कारण जन कल्याणकारी कार्यक्रमो मे भी कटौती करनी पड़ती है।
- नक्सलवादीयो की गतिविधीयो के कारण सामाजिक परिवेश मे असुरक्षा की भावना विद्यमान रहते है जिसके परिणाम सामाजिक विकास की गति विशेष रूप से बाधित होती है।

नक्सलवाद की समाप्ति के समाधान

- एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू की जानी चाहिए जो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये तथा देश प्रेम की भावना जागृत करने का प्रयास करे।
- जनसाधारण को राजनीति की मूलधार मे लाने हेतू ऐसे प्रयास किये जाये कि राजनिति को परिचित कराने और उससे जोड़ने का प्रयास करना चाहिए जिससे समूचे राष्ट्र मे सुनामी रचनात्मक क्रान्तिकारी परिवर्तन लाया जा सके।
- बॉर्डर एरिया डवपपमेन्ट प्रोग्राम एवं राष्ट्रीय रोजगार कानून को नक्सल प्रभावित जिलो में प्राथमिकता से लागू किया जाये।
- लोगो की जायेज मांगो को तत्काल पूरा करना तथा नाजायज मांगो को कोई स्थान न देना चाहिए।
- पुलिस तथा अर्द्व सैन्य बलो की अत्याधुनिक हथियारो को चलाने का तथा प्रति छापामार कार्यवाहियो के प्रशिक्षण किया जाये।
- सरकार द्वारा संचालित योजनाओ को यथाशीघ्र नक्सली क्षेत्रो मे क्रियान्वयन किया जाये। जिससे जनता को सरकार पर भरोसा हो।
- गुप्तचर व्यवस्था को चुस्त दुरस्त किया जाये ।
- नक्सली प्रभावित राज्य सरकारों द्वारा नक्सली गुटों के साथ शांति वार्ता करनी चाहिए।
- इलेक्ट्रोनिक मीडिया और प्रिन्ट मीडिया को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए जिससे जनता मे आक्रोश न फेलते हुए एक सही सकारात्मक सोच देश के प्रति जागृत हो।
- प्रशासनिक ढॉचे को अधिक पारदर्शी उत्तरदायीत्वपूर्ण तथा संवेदनशील बनाया जाये ताकि आम नागरिक इस पर विश्वास कर सके।
- नक्सलवाद की समस्या के समाधान हेतू केन्द्र सरकार द्वारा एकीकृत समाधान हेतु निती बनाई जाये जिससे नक्सल प्रभावित राज्यो की अहम भूमिका निहित हो और प्रभावित राज्य पारदर्शिता के साथ अपने दायित्व का विर्वहन कर सके।
- पिछड़ा जिला पहल (वी. डी. आई.) तथा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (वी. आर. जे. एफ.) का गठन किया जाना चाहिए।
- समन्वय केन्द्र की स्थापना पर बल दिया जाना जाहिए।
- नक्सलवाद का राजनीतीकरण नही किया जाये।
- नक्सली प्रभावित राज्यो की सरकारे तथा राजनीतिक दलो को अपने निजी स्वार्थ आधारित राजनीति नही करनी चाहिए। इस समस्या को एक हथियार के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए।
- नक्सलवाद समस्या के समाधान के लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक आदि सभी महत्वपूर्ण पहलूओ पर गहन अध्ययन की आवश्यकता है।
- नौकरशाही व्यवस्थाओ मे बदलाव समझाने का कार्य एवं जरूरत पड़ने पर सशस्त्र कार्यवाही समन्वित एवं सन्तुलित रूप से करके ही नक्सलवाद को नियन्त्रण मे लाया जा सकता है।
- सरकार अपने लोकतान्त्रिक धर्म के तहत बातचीत के शान्तिपूर्ण रास्ते पर चलकर नक्सलवाद की समस्या का निदान करे।
- नक्सलवाद की समस्या के समाधान के लिए हम सबको आगे बढकर काम करने की जरूरत है और उनके नेटवर्क बहुत मजबूत है इसके लिऐ ज्यादा जरूरी है कि हम अपने खुफिया तन्त्रो को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करे जिससे कि आवयकता पड़ने पर संकट दूर करने हेतू उनका पूरा सहयोग प्राप्त हो सके।
- नक्सली अग्रवाद के प्रभाव को कम करने का सबसे प्रभावी उपाय शिक्षा का प्रचार प्रसार है जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष सामाजिक, आर्थिक स्तर को सुधारा जा सकता है।
- नक्सली समस्या को सिर्फ पुलिस बल या ताकत के बल पर खत्म नही किया जा सकता आदिवासियो के सामाजिक, आर्थिक पहलूओ पर भी ध्यान देना होगा।

निष्कर्ष

भारत में व्याप्त आतंकवाद का नया रूप नक्सलवाद भारतीय संस्कृति एकता विभिन्नता व अखण्डता के लिऐ एक खतरा है यह कड़वी सच्चाई स्वीकार करनी होगी कि अब भारत मे नक्सलवाद एक नये प्रकार की आतंकवाद की प्रयोगशाला बन गया है चाहे इसके बाहरी आन्तरिक तंत्रो की दुर्बलता हो या बाहरी तत्वो की दुर्भावनाओ उत्तरदायी हो। अतः अगर इस आतंकवाद का मुकाबला परम्परागत उपायो से सम्भव नही किया जा सकता इसके लिए केवल कानून व्यवस्था बनाने से काम नही चलेगा बल्कि इसके लिए समन्वित राजनीति अपनाकर काम करने का समय आ गया है। आतंकवाद का अंत समन्वित सामुहिक सामूदायिक एवं सांसारिक स्तर पर करने का समय आ गया है किसी दुसरे पर आश्रित होकर अब काम नही चलने वाला अतः जरूरत है स्वयं समाज राष्ट्र व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक व समन्वित प्रयास करने की।

2014, RHIMRJ, All Rights Reserved
ISSN: 2349-7637 (Online)

–: सन्दर्भ सूची :–

- हुसैन, माजिद.(2009).'भारत का भूगोल' टाटा मेग्रा हिल्स, सीरीज पृ.सं. 16–12.
- प्रतियोगिता दर्पण. (2009).मासिक पत्रिका,दिसम्बर, पृ.सं. 886.
- इण्डिया टूडे 'लाल आतंक से मुकाबला' अक्टूबर 2009, पृ. सं. 5–6.
- शुक्ल, कृष्णानन्द. (2011).'नक्सलवाद बनाम आन्तरिक सुरक्षा'नई दिल्ली,राधा पब्लिकेशन, पृसं. 53–153.
- शुक्ल, कृष्णानन्द. (2011).'आन्तरिक सुरक्षा की चुनौतियॉ' नई दिल्ली, राधा पब्लिकेशन, पृसं. 72–124.
- सहगल,विनोद.(2004).अर्न्तराष्ट्रीय आतंकवाद. नई दिल्ली, प्रभात प्रकाशन, पृ.सं. 10–11.
- शुक्ल, के. एम. (2011).रक्षा अनुसंधान. इलाहबाद, पब्लिकेशनइलाहबाद, पृ.सं. 56–57.
- प्रतियोगिता दर्पण (2012). मासिक पत्रिका, अक्टूबर, पृ.सं. 556–560.
- क्रोनिकल (2012). मासिक पत्रिका, नवम्बर, पृ.सं. 25–29.
- राजस्थान पत्रिका (2014). कोटा, संपादकीय पृ. कोटा संस्करण, नवंबर,, 17–19.
- राजस्थान पत्रिका (2014). जयपुर, संपादकीय पृ. जयपुर संस्करण, नवंबर,15–17.
- सिंह, आर. के. (2014). भारतीय आन्तरिक सुरक्षा के मुद्दे और चुनौतियां, नई दिल्ली, सनराइज प्रकाशन.
- प्रतियोगिता दर्पण (2014). मासिक पत्रिका, अक्टूबर, पृ.सं. 776–780.

2014, RHIMRJ, All Rights Reserved
ISSN: 2349-7637 (Online)